भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451] No. 451] दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 12, 2017/अग्रहायण 21, 1939

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 379

DELHI, TUESDAY, DECEMBER 12, 2017/AGRAHAYANA 21, 1939

[N.C.T.D. No. 379

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सेवाएं विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2017

सं. फा. 20/13/2017/एस-1/एलआईटी/3726-3734.—इस संबंध में जारी पूर्ववर्ती समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त विभागों तथा/या लोक प्राधिकारियों के मामलों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या भारत संघ के विरूद्ध किसी वाद अपील, सीडब्ल्यूपी, सीसीपी, आरएफए तथा एलपीए, ओए, एमए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के लिये श्रीमती अवनीश अहलावत को स्थायी काउंसिल के रूप में नियुक्त करते हैं, जिनका प्रतिवाद इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये सरकार द्वारा शुरू किया जा चुका है। जिनका प्रतिवाद प्रारंभ में इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये किया गया है।

स्थायी काउंसिल के रूप में श्रीमती अवनीष अहलावत की नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह के नोटिस पर समाप्य है। नियुक्ति, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा समय—समय पर यथाविनिर्धारित द्वारा जारी दिल्ली उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिये 26 फरवरी, 1992 की अधिसूचना सं. फा. 5(10)/91/वि0/1345 में यथाअन्तर्विष्ट शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार होगी।

SERVICES DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 11th December, 2017

No. F.20/13/2017/S-1/Lit/3726-3734.—In supersession of all previous notifications issued earlier in this regard and in exercise of the powers conferred under sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Smt. Avnish Ahlawat as Standing Counsel for the High Court of Delhi at New Delhi in relation to any Suit, Appeal, CWP, CCP, RFAs and LPAs, OA, MA etc. and other proceedings by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs connected with "Services" matters of all departments of Government of National Capital Territory of Delhi and/or public officer(s), whose defence has been undertaken by it initially for a period of one year from the date of this notification.

The appointment of Smt. Avnish Ahlawat as Standing Counsel is terminable on one month notice on either side. The appointment is subject to the terms and conditions as contained in the Notification No.F.5/10/91-Lit./1345 dated 26th February, 1992 for the High Court and Central Administrative Tribunal issued by the Department of Law, Justice & Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi and also as may be prescribed, from time to time.

सं. फा. 20/13/2017/एस-1/एलआईटी/3735-3745.—इस संबंध में जारी पूर्ववर्ती समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त विभागों तथा/या लोक प्राधिकारियों के मामलों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या भारत संघ के विरुद्ध किसी वाद अपील, सीडब्ल्यूपी, सीसीपी, आरएफए तथा एलपीए, ओए, एमए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के लिये निम्नलिखित अधिवक्ताओं को अपर स्थायी काउंसिल के रूप में नियुक्त करते हैं, जिनका प्रतिवाद प्रारंभ में इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अविध के लिये किया गया है।

- 1. श्री यीषु जैन
- 2. डॉ. जोहेब हुसैन

उक्त नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह के नोटिस पर समाप्य है। नियुक्ति, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा समय—समय पर यथाविनिर्धारित द्वारा जारी दिल्ली उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिये 26 फरवरी, 1992 की अधिसूचना सं. फा. 5(10)/91/वि./1345 में यथाअन्तर्विष्ट शर्ती एवं निबंधनों के अनुसार होगी।

No. F. 20/13/2017/S-1/Lit/3735-3745.—In supersession of all previous notifications issued earlier in this regard and in exercise of the powers conferred under sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Advocates as Additional Standing Counsel for the High Court of Delhi at New Delhi in relation to any Suit, Appeal, CWP, CCP, RFAs and LPAs, OA, MA etc. and other proceedings by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs connected with "Services" matters of all departments of Government of National Capital Territory of Delhi and/or public officer(s), whose defence has been undertaken by it initially for a period of one year from the date of this notification.

- 1. Sh. Yeeshu jain
- 2. Dr. Zoheb Hossain

The above appointment is terminable on one month notice on either side. The appointment is subject to the terms and conditions as contained in the Notification No. F. 5/10/91-Lit./1345 dated 26th February, 1992 for the High Court and Central Administrative Tribunal issued by the Department of Law, Justice & Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi and also as may be prescribed, from time to time.

सं. फा. 20/13/2017/एस-1/एलआईटी/3746-3754.—इस संबंध में जारी पूर्ववर्ती समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त विभागों तथा/या लोक प्राधिकारियों के मामलों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या भारत संघ के विरुद्ध किसी वाद अपील, सीडब्ल्यूपी, सीसीपी, आरएफए तथा एलपीए, ओए, एमए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के लिये निम्नलिखित अधिवक्ताओं को पैनल काउंसिल के रूप में नियुक्त करते हैं, जिनका प्रतिवाद प्रारंभ में इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अविध के लिये किया गया है।

- 1. सुश्री मिनी पुष्करणा
- 2. श्रीमती विभा महाजन सेठ
- 3. श्री सुब्रमनियम बीकेवी
- 4. श्रीमती रश्मी चोपडा
- श्री गौरव ढ़ींगरा
- 6. श्री नौषाद अहमद खान
- 7. श्री वी. बालाजी
- सुश्री रूचिरा गुप्ता
- 9. सुश्री लतिका चौधरी
- 10. श्रीमती रचना श्रीवास्तव
- 11. श्री सुजीत कुमार मिश्र

उक्त नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह के नोटिस पर समाप्य है। नियुक्ति, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा समय—समय पर यथाविनिर्धारित द्वारा जारी दिल्ली उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिये 18 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. फा. 5(2)/07/वि./ 303—310 में यथाअन्तर्विष्ट शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार होगी।

No. F. 20/13/2017/S-I/Lit/3746-3754.—In supersession of all previous notifications issued earlier in this regard and in exercise of the powers conferred under sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Advocates as Panel Counsel for the High Court of Delhi at New Delhi in relation to any Suit, Appeal, CWP, CCP, RFAs and LPAs, OA, MA etc. and other proceedings by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs connected with "Services" matters of all departments of Government of National Capital Territory of Delhi and/or public officer(s), whose defence has been undertaken by it initially for a period of one year from the date of this notification.

- 1. Ms. Mini Pushkarna
- 2. Mrs. Vibha Mahajan Seth
- 3. Sh. Subrahmanyam BKV
- 4. Smt. Rashmi Chopra
- 5. Sh. Gaurav Dhingra
- 6. Sh. Naushad Ahmed Khan
- 7. Sh. V. Balaji
- 8. Ms. Ruchira Gupta

- 9. Ms. Latika Choudhury
- 10. Smt. Rachana Srivastava
- 11. Sh. Sujeet Kumar Mishra

The above appointment is terminable on one month notice on either side. The appointment is subject to the terms and conditions as contained in the Notification No. F. 5(2)/07/Lit./303-310 dated 18th March 2008 for the High Court and Central Administrative Tribunal issued by the Department of Law, Justice & Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi and also as may be prescribed, from time to time.

सं. फा. 20/13/2017/एस-1/एलआईटी/3755-3763.—इस संबंध में जारी पूर्ववर्ती समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त विभागों तथा/या लोक प्राधिकारियों के मामलों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या भारत संघ के विरुद्ध किसी वाद अपील, सीडब्ल्यूपी, सीसीपी, आरएफए तथा एलपीए, ओए, एमए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के लिये श्री आर. एन. सिंह को स्थायी काउंसिल के रूप में नियुक्त करते हैं, जिनका प्रतिवाद प्रारंभ में इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये किया गया है।

नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह के नोटिस पर समाप्य है। नियुक्ति, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा समय—समय पर यथाविनिर्धारित द्वारा जारी दिल्ली उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिये 26 फरवरी, 1992 की अधिसूचना सं. फा. 5(10)/91/वि0/1345 में यथाअन्तर्विष्ट शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार होगी।

No. F. 20/13/2017/S-I/Lit/3755-3763.—In supersession of all previous notifications issued earlier in this regard and in exercise of the powers conferred under sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. R. N. Singh as Standing Counsel for Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, Delhi in relation to any Suit, Appeal, CWP, CCP, RFAs and LPAs, OA, MA etc. and other proceedings by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs connected with "Services" matters of all departments of Government of National Capital Territory of Delhi and/or public officer(s), whose defence has been undertaken by it initially for a period of one year from the date of this notification.

The above appointment is terminable on one month notice on either side. The appointment is subject to the terms and conditions as contained in the Notification No.F.5/10/91-Lit./1345 dated 26th February, 1992 for the High Court and Central Administrative Tribunal issued by the Department of Law, Justice & Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi and also as may be prescribed, from time to time.

सं. फा. 20/13/2017/एस-1/एलआईटी/3764-3776.—इस संबंध में जारी पूववर्ती समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त विभागों तथा/या लोक प्राधिकारियों के मामलों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या भारत संघ के विरुद्ध किसी वाद अपील, सीडब्ल्यूपी, सीसीपी, आरएफए तथा एलपीए, ओए, एमए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के लिये निम्नलिखित अधिवक्ताओं को अपर स्थायी काउंसिल के रूप में नियुक्त करते हैं, जिनका प्रतिवाद प्रारंभ में इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अविध के लिये किया गया है।

- 1. श्री एच.ए. खान
- 2. श्रीमती ईशा मजुमदार
- 3. श्री अमित शर्मा

4. श्रीमती हरविन्द्र ओबराय

उक्त नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह के नोटिस पर समाप्य है। नियुक्ति, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा समय—समय पर यथाविनिर्धारित द्वारा जारी दिल्ली उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिये 26 फरवरी, 1992 की अधिसूचना सं. फा. 5(10)/91/वि./ 1345 में यथाअन्तर्विष्ट शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार होगी।

No. F. 20/13/2017/S-1/Lit/3764-3776.—In supersession of all previous notifications issued earlier in this regard and in exercise of the powers conferred under sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Advocates as Additional Standing Counsel for the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, Delhi in relation to any Suit, Appeal, CWP, CCP, RFAs and LPAs, OA, MA etc. and other proceedings by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs connected with "Services" matters of all departments of Government of National Capital Territory of Delhi and/or public officer(s), whose defence has been undertaken by it initially for a period of one year from the date of this notification.

- 1. Sh. H. A. Khan
- 2. Mrs. Esha Mazumdar
- 3. Sh. Amit Sharma
- 4. Mrs. Harvinder Oberoi

The above appointment is terminable on one month notice on either side. The appointment is subject to the terms and conditions as contained in the Notification No.F.5/10/91-Lit./1345 dated 26th February, 1992 for the High Court and Central Administrative Tribunal issued by the Department of Law, Justice & Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi and also as may be prescribed, from time to time.

सं.फा. 20/13/2017/एस-1/एलआईटी/3777-3785.—इस संबंध में जारी पूर्ववर्ती समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में तथा सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) की धारा 2 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समस्त विभागों तथा/या लोक प्राधिकारियों के मामलों के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा/या भारत संघ के विरुद्ध किसी वाद अपील, सीडब्ल्यूपी, सीसीपी, आरएफए तथा एलपीए, ओए, एमए इत्यादि तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के लिये निम्नलिखित अधिवक्ताओं को अपर पैनल काउंसिल के रूप में नियुक्त करते हैं, जिनका प्रतिवाद प्रारंभ में इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये किया गया है।

- 1. श्री हरि दत्त शर्मा
- 2. सुश्री प्रियंका मित्रा भारद्वाज
- 3. श्री प्रदीप कुमार
- 4. श्री प्रताप शंकर
- 5. श्री मनंजय कुमार मिश्र
- 6. श्री विक्रान्त नारायण वस्देव
- 7. श्री अवनीश क्मार
- 8. श्री जगदीश एन
- 9. श्री सूर्य नाथ पाण्डेय
- 10. श्री अमित यादव

- 11. सुश्री प्रतिमा के.गुप्ता
- 12. श्री कपिल अग्निहोत्री
- 13. श्री सौरभ चड्डा
- 14. श्री गिरीश चन्द्र झा
- 15. श्री समीर शर्मा
- 16. श्री उज्जवल कुमार झा
- 17. सुश्री सरिता अग्रवाल
- 18. श्री अमित आनंद
- 19. सुश्री दीपिका
- 20. श्री अनुज कुमार शर्मा
- 21. सुश्री पूर्णिमा माहेश्वरी
- 22. श्री श्वेतांक शान्तन्
- 23. श्री अतुल कुमार
- 24. श्री सिद्धार्थ पांडा
- 25. श्री रजनीश कुमार शर्मा

उक्त नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक माह के नोटिस पर समाप्य है। नियुक्ति, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा समय—समय पर यथाविनिर्धारित द्वारा जारी दिल्ली उच्च न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिये 18 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. फा. 5(2)/02/वि0/303—310 में यथाअन्तर्विष्ट शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर, डी. कार्तिकेयन, उपसचिव (सेवाएँ)

No. F. 20/13/2017/S-1/Lit/3777-3785.—In supersession of all previous notifications issued earlier in this regard and in exercise of the powers conferred under sub-section (7) of Section 2 of the Code of Civil Procedure, (5 of 1908) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Advocates as Panel Counsel for Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, Delhi in relation to any Suit, Appeal, CWP, CCP, RFAs and LPAs, OA, MA etc. and other proceedings by or against the Government of National Capital Territory of Delhi and/or Union of India in relation to the affairs connected with "Services" matters of all departments of Government of National Capital Territory of Delhi and/or public officer(s), whose defence has been undertaken by it initially for a period of one year from the date of this notification.

- 1. Sh. Hari Datt Sharma
- 2. Ms. Priyanka Mitra Bhardwaj
- 3. Sh. Pradeep Kumar
- 4. Sh. Pratap Shanker
- 5. Sh. Mananjay Kumar Mishra
- 6. Sh. Vikrant Narayan Vasudeva
- 7. Sh. Awanish Kumar

- 8. Sh. Jagdish N
- 9. Sh. Surya Nath Pandey
- 10. Sh. Amit Yadav
- 11. Ms. Pratima K. Gupta
- 12. Sh. Kapil Agnihotri
- 13. Sh. Saurabh Chadda
- 14. Sh. Girish Chandra Jha
- 15. Sh. Sameer Sharma
- 16. Sh. Ujjwal Kumar Jha
- 17. Ms. Sarita Aggarwal
- 18. Sh. Amit Anand
- 19. Ms. Deepika
- 20. Sh. Anuj Kumar Sharma
- 21. Ms. Purnima Maheshwari
- 22. Sh. Swetank Shantanu
- 23. Sh. Atul Kumar
- 24. Sh. Siddharth Panda
- 25. Sh. Rajneesh Kumar Sharma

The above appointment is terminable on one month notice on either side. The appointment is subject to the terms and conditions as contained in the Notification No. F. 5(2)/07/Lit./303-310 dated 18th March, 2008 for the High Court and Central Administrative Tribunal issued by the Department of Law, Justice & Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi and also as may be prescribed, from time to time.

By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

D. KARTHIKEYAN, Dy. Secy. (Services)